NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□□

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 18 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	IMEC के लिए फ़िलिस्तीनी मुद्दे का समाधान ज़रूरी: मिस्र के विदेश मंत्री
Page 05 Syllabus : GS 3 : Science and Tech / Prelims	नासिक यूनिट खुली; HAL साल में 24 तेजस जेट बना सकता है
Page 06 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	चीन और भारत की अगुवाई में बेहतर ग्लोबल गवर्नेंस
Page 09 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	ग्रीन बयानबाज़ी बनाम असलियत
In News Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	नॉन-अलाइंड मूवमेंट (NAM)
Page 06 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	नई दिल्ली दौरे के बाद अफ़गानिस्तान के लिए अगले कदम

Page 03 : GS 2 : International Relations / Prelims

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए भारत की अपनी यात्रा के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के पुनरुद्धार के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे पर प्रगति आवश्यक है। आईएमईसी, जिसे मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाली एक परिवर्तनकारी कनेक्टिविटी परियोजना के रूप में परिकल्पित किया गया था, चल रहे गाजा संघर्ष के बीच ठप हो गया है। अब्देलट्टी ने भारत को मिस्र के स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (एससीजेडओएन) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, व्यापार, औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी में व्यापक सहयोग पर प्रकाश डाला।

Resolution of Palestinian question necessary for IMEC: Egyptian FM

In Delhi for the first India-Egypt Strategic Dialogue, Abdelatty urges India to join the Egyptian Suez Canal Economic Zone; meets Jaishankar, calls on PM Modi; IMEC project, unveiled at the G-20 Summit in 2023, stalled soon after due to Gaza war

Suhasini Haidar
NEW DELHI

Plans for the India-Middle East-Europe-Economic Corridor (IMEC) cannot proceed without some progress on the Palestinian question, Egypt's Foreign Minister Badr Abdelatty said on Friday, adding that Egypt would be interested to join all such connectivity projects once the situation is "conducive".

Mr. Abdelatty told a group of presspersons that he had discussed the IMEC project with External Affairs Minister S. Jaishankar during the first India-Egypt Strategic Dialogue on Friday, and also proposed that India join the Egyptian Suez Canal Economic Zone (SCZONE), where Russia, China, and a few other countries already have separate industrial complexes.

On Friday, he called on Prime Minister Narendra Modi, who praised Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi for the Gaza Peace Plan signed with U.S. President Donald Trump this week.

Derailed by attacks

The IMEC was launched during the G-20 in New Delhi in September 2023 by a number of countries including India, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, the U.S., and the European Union, and is meant to be routed via Israel's Haifa port. The project floundered within a month, however, after the October 7 terror attacks in Israel and the Israeli bombardment of Gaza.

While welcoming all connectivity projects "between the east and west", Mr. Abdelatty said that the aspirations of the Palestinian people for their own State was necessary for peace and security in the region, and it would not be possible to run a cross-regional connectivity project like the IMEC without it.

Building relations: Prime Minister Narendra Modi meeting Foreign Minister of Egypt Badr Abdelatty in New Delhi on Friday. PTI

"If we are serious about having final peace and security, a comprehensive deal and the security for Israel and the whole region, the only solution is to respond positively to the legitimate aspirations of the Palestinian people to have their own statehood, to have their own independent state," Mr. Abdelatty said in response to a question from *The Hindu*.

Indian industrial zone

Turning to bilateral matters, Mr. Abdelatty said that India and Egypt have committed to doubling bilateral trade from the present level of $5 billion, with particular potential in the areas of chemicals, minerals, pharmaceuticals, phosphates, digital technology, artificial intelligence, and renewable energy.

"We have a special industrial zone for China and for Russia in the SCZONE and we are encouraging an Indian industrial zone where we would provide all facilitation and incentives to Indian companies," he said, adding that India would be able to export goods beyond Egypt, with its population of 120 million, to a market of more than "two billion inhabitants" across Africa, South America, Europe, and Arab countries that are connected to Egyptian ports through free trade agreements.

समस्या अवलोकन

- मुख्य चिंता: G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू की गई IMEC परियोजना, क्षेत्रीय स्थिरता के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है - जो फिलिस्तीनी प्रश्न को हल करने पर निर्भर करती है।
- भू-राजनीतिक संदर्भ: इज़राइल-गाजा युद्ध के बाद इज़राइल के हाइफ़ा बंदरगाह के माध्यम से परियोजना का मार्ग राजनीतिक और तार्किक रूप से अव्यवहार्य हो गया।
- मिस्र का रुख: काहिरा इस बात पर जोर देता है कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा एक स्वतंत्र राज्य के लिए फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को स्वीकार करने पर निर्भर करती है।
- भारत की भूमिका: IMEC के एक प्रमुख हितधारक के रूप में भारत से आग्रह किया जाता है कि वह फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे और इज़राइल के साथ बढ़ते संबंधों के लिए अपने पारंपरिक समर्थन के साथ अपनी कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करे।

मुख्य अवलोकन

- राजनयिक अंतर्दृष्टि: मिस्र स्वेज नहर के माध्यम से खुद को एक शांति दलाल और रसद केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो इसके रणनीतिक महत्व को मजबूत करता है।
- आर्थिक अवसर: SCZONE में भारत की संभावित भागीदारी मिस्र के व्यापक व्यापार संबंधों के माध्यम से अफ्रीकी, यूरोपीय और अरब बाजारों तक पहुंच की अनुमति देगी।
- कनेक्टिविटी व्यवधान: गाजा युद्ध ने IMEC की प्रारंभिक गति को पटरी से उतार दिया, यह रेखांकित करते हुए कि कैसे भू-राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक परियोजनाओं को कमजोर करती है।
- रणनीतिक संवाद: भारत-मिस्र साझेदारी उभरते क्षेत्रों - एआई, नवीकरणीय और डिजिटल प्रौद्योगिकी में विविधता ला रही है - जो पारंपरिक व्यापार से परे आपसी हितों को दर्शाती है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत की पश्चिम एशिया नीति	इज़राइल, फिलिस्तीन और अरब राज्यों के साथ संबंधों को संतुलित करना।
कनेक्टिविटी कॉरिडोर	चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के काउंटर के रूप में आईएमईसी।
स्वेज नहर की भू-राजनीति	समुद्री व्यापार और वैश्विक रसद में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका।
भारत-मिस्र संबंध	2023 के बाद बढ़ता सहयोग: रणनीतिक संवाद।
वैश्विक शांति और सुरक्षा	स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक शर्त के रूप में फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- भू-राजनीतिक निहितार्थ: IMEC की सफलता मध्य पूर्वी स्थिरता पर निर्भर करती है; अनसुलझे संघर्ष बुनियादी ढांचे की कूटनीति को नाजुक बनाते हैं।
- राजनयिक संतुलन: भारत को रणनीतिक व्यावहारिकता का अनुसरण करना चाहिए – इजरायल के साथ संबंधों को बनाए रखना चाहिए और साथ ही शांति प्रयासों का समर्थन करना चाहिए जो उसकी गुटनिरपेक्ष विरासत के साथ संरेखित हैं।
- आर्थिक रणनीति: मिस्र का SCZONE भारत को नए बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिससे चीन-केंद्रित मार्गों पर निर्भरता कम होती है।

- क्षेत्रीय नेतृत्व: मिस्र आर्थिक सहयोग को शांति निर्माण से जोड़कर अरब भू-राजनीति में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करता है।

समाधान और नीति महत्व

- शांति कूटनीति: पश्चिम एशिया को स्थिर करने के लिए दो-राज्य समाधान के लिए नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव।
- रणनीतिक भागीदारी: SCZONE में भारत का निवेश IMEC का पूरक हो सकता है, जिससे वैकल्पिक व्यापार कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकती है।
- विविध जुड़ाव: द्विपक्षीय व्यापार को तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और एआई में विस्तारित करने से आर्थिक लचीलापन मजबूत होता है।
- बहुपक्षीय सहयोग: शांतिपूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण की वकालत करने के लिए G20, BRICS और UN मंचों का उपयोग करें।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
क्षेत्रीय स्थिरता	अंतरमहाद्वीपीय कनेक्टिविटी के लिए गाजा में शांति आवश्यक।
भारत की विदेश नीति	बदलते गठबंधनों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता का परीक्षण।
व्यापार और लॉजिस्टिक्स	स्वेज नहर भारत-यूरोप आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नोड बनी हुई है।
वैश्विक कूटनीति	शांति और आर्थिक सहयोग की अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालता है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग	मिस्र और भारत संयुक्त रूप से विकास-संचालित कूटनीति का समर्थन कर सकते हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- लंबे समय तक गाजा संघर्ष और राजनीतिक विखंडन।
- IMEC भागीदारों (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच अलग-अलग हित।
- जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बिना IMEC के प्रतीकात्मक होने का जोखिम।
- वास्तविक राजनीति (इज़राइल) के साथ नैतिक कूटनीति (फिलिस्तीन) को संतुलित करने की आवश्यकता।
- चीन के बीआरआई और समानांतर कनेक्टिविटी पहलों के साथ प्रतिस्पर्धा।

निष्कर्ष:

भारत और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में आईएमईसी का वादा न केवल बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति और राजनीतिक समाधान पर भी निर्भर करता है। फिलिस्तीनी प्रश्न को संबोधित करने पर मिस्र का जोर इस बात को रेखांकित करता है कि संघर्ष के बीच आर्थिक एकीकरण पनप नहीं सकता है। भारत के लिए, एससीजोन भागीदारी और राजनयिक वार्ता के माध्यम से मिस्र के साथ संबंधों को गहरा करना रणनीतिक और नैतिक दोनों तरह के लाभांश प्रदान करता है। एक स्थिर मध्य पूर्व अंततः यह निर्धारित करेगा कि क्या आईएमईसी सहयोग के प्रतीक के रूप में विकसित होता है या अनसुलझे भू-राजनीति का शिकार बना रहता है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे नई दिल्ली में 2023 G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।

2. इसका उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ना है।

3. कॉरिडोर के इजरायल के हाइफा बंदरगाह से गुजरने की उम्मीद है।

4. मिस्र IMEC के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर : b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: यूरोप और अफ्रीका के साथ आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी प्राप्त करने में भारत के लिए एक रणनीतिक भागीदार के रूप में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) की क्षमता का मूल्यांकन करें। **(150 शब्द)**

Page 05 : GS 3 : Science and Tech / Prelims

एचएएल के नासिक संयंत्र में तेजस एमके1ए की तीसरी उत्पादन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40 (एचटीटी-40) की दूसरी लाइन का उद्घाटन रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल भारत की व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और मेक इन इंडिया उद्देश्यों के साथ संरेखित स्वदेशीकरण, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को दर्शाती है।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Nashik unit open; HAL can roll out 24 Tejas jets a year

Rajnath Singh flags off the first light combat aircraft Mk1A produced at the facility; Minister opens the third production line for the fighter and the second of Hindustan Turbo Trainer-40 aircraft

Saurabh Trivedi
Hemanth C.S.
NASHIK

The production lines of the light combat aircraft Tejas Mk1A and the training aircraft HTT-40 are proof of the synergy among government, industry and academia, Defence Minister Rajnath Singh said here on Friday, asserting that no challenge was too big if faced together.

He was speaking after inaugurating the third production line of Tejas Mk1A and the second of the Hindustan Turbo Trainer-40 at the Hindustan Aeronautics Ltd. facility.

The Defence Minister flagged off the first LCA Mk1A aircraft produced at the facility, describing it as a symbol of India's growing self-reliance in defence.

Highlighting the transformation of India's defence sector in the past decade under Prime Minister Narendra Modi's leadership, Mr. Singh said the country, which once imported 65-70% of its military hardware, now manufactured nearly 65% of it domestically. "Our goal is to increase this to 100% in the near future," he said.

Coming on stream: Rajnath Singh during the flagging off of new production lines at HAL in Nashik on Friday. @SPOKESPERSONMOD X

He recalled that when the government under Mr. Modi came to power in 2014, it faced numerous challenges such as limited defence preparedness, import dependence, and a lack of private sector participation.

"Earlier, defence production was largely confined to government enterprises. There was insufficient focus on planning, advanced technology, and innovation, which made us dependent on other nations and created strategic vulnerabilities," he said. "These challenges pushed us to adopt new thinking and reforms. Today, we are manufacturing domestically what we used to import – fighter jets, missiles, engines, and electronic warfare systems."

Mr. Singh reaffirmed the government's commitment to inducting indigenous technologies into the armed forces and hailed HAL as the backbone of India's defence manufacturing ecosystem. He commended HAL for supporting the recently decommissioned MiG-21 fleet and its pivotal role during Operation Sindoor.

"In our security history, few instances have tested our system as much as Operation Sindoor. HAL provided round-the-clock support to the Indian Air Force, ensuring operational readiness. The Nashik team carried out crucial integration of the BrahMos missile on Su-30 aircraft, which destroyed terrorist hideouts during the operation," he said.

"This proved that India can design, produce, and deploy its own systems effectively," he added.

HAL plans

The first two production lines of the LCA and the first production line of the HTT-40 are in Bengaluru. The company initiated establishment of the third production line to fast-track delivery of Tejas to the IAF. The production line in Nashik has a capacity of eight aircraft a year.

The company said that with the third production line, HAL would achieve a total production capacity of 24 aircraft per year for LCA Mk1A.

The third Line had resulted in creation of approximately 1,000 jobs, and development of more than 40 industry partners in and around Nashik, including in cities of Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. In two years, the company plans to expand capacity in Nashik up to 10 aircraft a year by way of establishing an additional Assembly Jig Line, Tooling and Pre-installation Check facilities for Line Replaceable Units.

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** आयातित रक्षा उपकरणों पर भारत की ऐतिहासिक निर्भरता, सीमित रणनीतिक स्वायत्तता और परिचालन तैयारी।
- **सरकारी पहल:** स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन लाइनों की स्थापना।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को आधुनिक लड़ाकू और ट्रेनर विमानों की तेजी से डिलीवरी, परिचालन तत्परता और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करना।

मुख्य अवलोकन

- **रक्षा स्वदेशीकरण:** भारत ने 65-70% सैन्य हार्डवेयर के आयात से लगभग 65% घरेलू स्तर पर निर्माण करने की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिसका लक्ष्य 100% आत्मनिर्भरता है।
- **एचएएल की भूमिका:** एचएएल भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र है, जो पिछले संचालन (जैसे, ऑपरेशन सिंदूर) के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।
- **क्षमता विस्तार:** नासिक उत्पादन लाइन में सालाना 8 तेजस एमके 1ए विमान जुड़ेंगे, जो प्रति वर्ष 24 विमानों के कुल अनुमानित उत्पादन में योगदान देंगे।
- **आर्थिक और रोजगार प्रभाव:** महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ~1,000 नौकरियों का सृजन और 40+ उद्योग भागीदारों की भागीदारी।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
रक्षा विनिर्माण	एलसीए एमके1ए और एचटीटी-40 के लिए एचएएल उत्पादन लाइनों का विस्तार घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाता है।
रणनीतिक स्वायत्तता	स्वदेशी लड़ाकू जेट उत्पादन आयात निर्भरता को कम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।
उद्योग-शिक्षा-सरकार का तालमेल	सहयोगात्मक दृष्टिकोण तकनीकी नवाचार और उत्पादन दक्षता को सक्षम बनाता है।
रोजगार और अर्थव्यवस्था	रक्षा उत्पादन केंद्र स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास का सृजन करते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा	आधुनिक विमानों को तेजी से शामिल करने से भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता में वृद्धि हुई है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **तकनीकी निहितार्थ:** कई उत्पादन लाइनों की स्थापना से नवाचार, उन्नत प्रणालियों के एकीकरण (उदाहरण के लिए, Su-30 पर ब्रह्मोस मिसाइल), और परिचालन तत्परता में तेजी आती है।
- **आर्थिक निहितार्थ:** स्थानीय उद्योग की भागीदारी और रोजगार सृजन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाते हैं और एमएसएमई विकास का समर्थन करते हैं।
- **रणनीतिक निहितार्थ:** घरेलू उत्पादन में वृद्धि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करती है, कमजोरियों को कम करती है और निवारक क्षमताओं को मजबूत करती है।
- **नीतिगत दृष्टिकोण:** 2014 के बाद सरकारी सुधार निजी क्षेत्र की भागीदारी, उन्नत योजना और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित हैं, जो भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार देते हैं।

समाधान और नीति महत्व

- **क्षमता निर्माण:** भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन लाइनों और आधुनिक असेंबली सुविधाओं का विस्तार करना।
- **निजी क्षेत्र का सहयोग:** आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई राज्यों में उद्योग भागीदारों को शामिल करना।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार:** उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वदेशी प्रणालियों का एकीकरण आत्मनिर्भरता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **दीर्घकालिक योजना:** वृद्धिशील विस्तार योजनाएं (उदाहरण के लिए, नासिक सुविधा की भविष्य के 10 विमान/वर्ष क्षमता) रणनीतिक रक्षा तैयारियों के साथ संरेखित होती हैं।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
रक्षा आत्मनिर्भरता	राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है और रणनीतिक कमजोरियों को कम करता है।
क्षेत्रीय रोजगार	नौकरियों और औद्योगिक समूहों का सृजन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है।
राष्ट्रीय गौरव और क्षमता	स्वदेशी डिजाइन, उत्पादन और तैनाती भारत के वैश्विक रक्षा कद को बढ़ाती है।
नीति और शासन	सरकार-उद्योग-अकादमिक सहयोग की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
सैन्य तैयारी	आधुनिक विमानों को तेजी से शामिल करने से वर्तमान और भविष्य के खतरों के लिए तत्परता सुनिश्चित होती है।

आगे की चुनौतियाँ

- गुणवत्ता बनाए रखते हुए भारतीय वायुसेना की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना।
- राज्यों में निजी क्षेत्र की क्षमताओं को कुशलतापूर्वक एकीकृत करना।
- अगली पीढ़ी के विमानों और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास को बनाए रखना।
- महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता का प्रबंधन।
- आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी प्राथमिकताओं को एक साथ संतुलित करना।

निष्कर्ष:

तेजस MK1A और HTT-40 के लिए HAL की नासिक उत्पादन लाइनों का शुभारंभ आयात निर्भरता से रक्षा आत्मनिर्भरता तक भारत की यात्रा पर प्रकाश डालता है। सरकार-उद्योग सहयोग के साथ स्वदेशी विनिर्माण में रणनीतिक निवेश, परिचालन तत्परता बढ़ाता है, रोजगार पैदा करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। रक्षा क्षमताओं के पूर्ण स्वदेशीकरण को प्राप्त करने के लिए निरंतर विस्तार, नवाचार और नीतिगत समर्थन आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वतंत्र रूप से उन्नत प्रणालियों का डिजाइन, उत्पादन और तैनाती कर सकता है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) नासिक सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसने तेजस एमके1ए के लिए तीसरी उत्पादन लाइन शुरू कर दी है।

2. नासिक संयंत्र का उद्देश्य प्रति वर्ष 24 तेजस विमानों का उत्पादन करना है।

3. नासिक के ऑनलाइन आने के बाद एचएएल अपनी बेंगलुरु सुविधा को बंद करने की योजना बना रहा है।

विकल्प:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) उपरोक्त सभी

उत्तर: a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में तेजस एमके1ए और HTT-40 के लिए HAL नासिक उत्पादन लाइनों के महत्व पर चर्चा करें।

Page 06 : GS 2 : International Relations / Prelims

चीन-भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ उभरती वैश्विक शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। चीन और भारत के नेताओं के बीच हाल ही में हुई व्यस्तता, विशेष रूप से एससीओ और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से, बहुध्रुवीयता, बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में इन दो एशियाई शक्तियों की भूमिका को उजागर करती है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव (जीजीआई) जैसी पहलों का उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार और मजबूती लाना है, जिससे एकतरफावाद, संरक्षणवाद और आधिपत्यवाद की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

Better global governance, led by China and India

The year 2025 marks the 75th anniversary of diplomatic ties between China and India. Since April 1, 1950, exchanges between the two great countries have come a long way, in which heads of state (government) diplomacy plays a key role in enhancing mutual trust, mutual respect and mutual complementarity. Highlighting more recent achievements are the interactions and friendship between the two leaders – China's President Xi Jinping and India's Prime Minister Narendra Modi. From 2014 to 2024, Mr. Xi and Mr. Modi have met 18 times. When the year 2014 was declared as the Year of China-India Friendly Exchanges, Mr. Xi paid a state visit to India in September and made a trip to Ahmedabad, the home town of Mr. Modi. China and India issued a Joint Statement on Building an Even Closer Partnership for Development. In May 2015, Mr. Modi made his first visit to China, and Mr. Xi received him in Xi'an, Mr. Xi's home town.

From 2016 to 2019, the two leaders met multiple times each year on the occasions of the BRICS summit, the G-20 summit, and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit. Affected by the COVID-19 pandemic, the next few years saw the two leaders exchange greetings and messages through letters and in telephone conversations. With the resumption of face-to-face meetings, Mr. Xi held talks with Mr. Modi on the sidelines of the BRICS summit in Johannesburg in August 2023. And in October 2024, the two leaders held a bilateral meeting on the sidelines of the 16th BRICS summit in Kazan, reaching important understandings on improving and growing China-India relations.

A milestone for the United Nations

This year also marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations, following the victory of the world anti-fascist war. Eighty years ago, upon deep reflection on the bitter lessons of the First and Second World Wars, the international community established the UN, commencing a brand new practice in global governance. In the past 80 years, the UN-based visions and practice of global governance have made historic contributions to maintaining world peace and development. However, the first few decades of the 21st century saw the world increasingly confronted with volatility, turbulence, uncertainty and unpredictability.

Faced with harmful "isms" such as unilateralism, protectionism, isolationism, separatism, terrorism, extremism and hegemonism, humanity needs to dwell on a major subject of our times, i.e., in order not to slip into a rule of jungle law, the kind of global governance system that needs to be built and how to reform and improve our global governance. Therefore, at such an important juncture, the 25th SCO Summit in Tianjin and the 19th in-person Xi-Modi meeting during the summit have been highly anticipated and expected by not only the more than 2.8 billion people in China and India but also the rest of the world, to shed some light on subjects such as bilateral relations, global governance and the future of humanity.

Qin Jie
is the Consul General of the People's Republic of China, in Mumbai

China-India cooperation can increase the strength of multilateralism in international affairs

Partners, not rivals

Indeed, as pointed out by Sudheendra Kulkarni, political adviser and scholar, the 2025 Tianjin SCO Summit could be one of the most successful in the organisation's history. This could be because of the changing world order (with the West rapidly losing its dominance in global affairs in the irreversible trend of multipolarity and multilateralism), and, more significantly, due to the growing importance of Asia and Eurasia. Mr. Xi and Mr. Modi are two leaders who have shown vision and wisdom in their friendly interactions.

Mr. Xi has emphasised that China and India shoulder the crucial responsibility of improving the well-being of the two peoples, promoting solidarity and rejuvenation of developing countries, and advancing the progress of human society. China and India should be good neighbours and partners who help each other succeed. He made four points of suggestion – China and India should strengthen strategic communication and deepen mutual trust; expand exchanges and cooperation to achieve mutual benefit and win-win; accommodate each other's concerns and get along in peace and harmony, and strengthen multilateral coordination to safeguard our shared interests. Mr. Modi echoed Mr. Xi in this by saying that the India-China relationship is back on a positive trajectory, that peace and stability in the border regions have been maintained, and that direct flights were to resume.

Such progress benefits not only the peoples of India and China but also the whole world. India and China are partners, not rivals. Their consensus far outweighs their disagreement. India-China cooperation will make the 21st century a genuine Asian century, and the two sides joining hands will increase the strength of multilateralism in international affairs.

The highlight of the Tianjin SCO summit was the Global Governance Initiative (GGI) raised by Mr. Xi, based on five basic principles. First, stay committed to sovereign equality. All countries, regardless of size, strength or wealth, shall have their sovereignty and dignity respected, their domestic affairs free from external interference, the right to independently choose their social system and development path, and the right to participate in, make decisions in and benefit from the global governance process as equals. Greater democracy should be promoted in international relations to make the global governance system better reflect the interests and the aspirations of the majority of countries, especially the developing countries.

Second, stay committed to international rule of law. The purposes and principles of the UN Charter are universally recognised basic norms of international relations and must be upheld unwaveringly. International law and rules must be applied, equally and uniformly, without any double standards or imposition. Major countries must take the lead in advocating and defending international rule of law.

Third, stay committed to multilateralism. Global affairs should be decided by all, the governance system built by all, and the fruits of governance shared by all. The UN is the core platform for practising multilateralism and advancing global governance, whose role must be enhanced, not weakened.

Fourth, stay committed to the people-centered approach. The people of all nations are the fundamental actors in global governance, and their well being its ultimate benefit. It must seek improvement through reforms in order to inspire a greater sense of fulfilment through accelerated common development, a greater sense of safety through more effective response to humanity's common challenges, and a greater sense of well being through advancing the common interests of different countries and communities.

Fifth, stay committed to real results. Effective global governance is essentially one that resolves real problems. It must address both the root causes and symptoms to find sustainable solutions. Developed countries should earnestly take on their responsibilities and provide more resources and public goods, while developing countries should pull together for strength and do their best for the world.

The task ahead

The GGI is another major initiative and public good offered by China. With the aim of addressing the deficit of global governance, the GGI stems from the purposes and principles of the UN Charter, and responds to the shared aspiration of most countries. To reform and improve global governance does not mean overturning the existing international order or to create another framework outside the current international system. Rather, the goal is to make the existing international system and institutions better in taking action, working effectively, adapting to changes, responding promptly and effectively to various global challenges, and serving the interests of all countries.

As key members of the SCO and BRICS, China and India should step up to shoulder their responsibility in improving global governance, upholding multilateralism, strengthening communication and coordination on major international and regional issues, and in defending international fairness and justice. They should follow the strategic guidance of their two leaders, bearing in mind the importance of the larger picture and long-term view, taking on the responsibility of improving the well-being of their peoples, and in promoting the solidarity and the rejuvenation of developing countries.

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** मौजूदा वैश्विक शासन ढांचे को बढ़ते एकतरफावाद, संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच वैधता और प्रभावशीलता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **द्विपक्षीय संदर्भ:** चीन-भारत सहयोग को क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में एक स्थिर कारक के रूप में देखा जाता है, जो 2.8 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त प्रभाव का लाभ उठाता है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** बहुपक्षीय निर्णय लेने में वृद्धि, विकासशील देशों की समान भागीदारी और वैश्विक चुनौतियों के स्थायी समाधान को बढ़ाना।

मुख्य अवलोकन

- **द्विपक्षीय जुड़ाव:** 2014-2024 तक, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ने 18 बार मुलाकात की, जिससे आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग मजबूत हुआ।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** SCO, BRICS और G20 शिखर सम्मेलनों के माध्यम से जुड़ाव वैश्विक शासन को आकार देने में एशिया और यूरेशिया के महत्व को रेखांकित करता है।
- **ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव (GGI):** इसका उद्देश्य संप्रभु समानता, कानून के शासन, बहुपक्षवाद, जन-केंद्रित दृष्टिकोण और वास्तविक परिणामों के आसपास मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार करना है।
- **सकारात्मक प्रक्षेपवक्र:** चीन-भारत सीमाओं पर शांति और स्थिरता, सीधी उड़ान बहाली और संवाद-उन्मुख समस्या-समाधान साझेदारी की कहानी को मजबूत करते हैं, प्रतिद्वंद्विता नहीं।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
कूटनीति और द्विपक्षीय संबंध	चीन-भारत उच्च स्तरीय बैठकों में रणनीतिक विश्वास और सहयोग में सुधार होता है।
बहुपक्षवाद	एससीओ, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित सुधार सहकारी निर्णय लेने को मजबूत करते हैं।
वैश्विक शासन	जीजीआई वर्तमान प्रणाली में वैधता, इक्विटी और प्रभावशीलता की कमी को संबोधित करता है।
क्षेत्रीय स्थिरता	एशिया-केंद्रित सहयोग यूरेशिया में शांति और विकास को बढ़ावा देता है।
विकासशील देश	पहल एकजुटता, कायाकल्प और साझा विकास लाभों पर जोर देती है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **सामरिक निहितार्थ:** चीन और भारत, प्रमुख एशियाई शक्तियों के रूप में, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने और विकासशील देशों की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तैनात हैं।
- **नीतिगत निहितार्थ:** GGI संप्रभुता, कानून, बहुपक्षवाद और जन-केंद्रित परिणामों के आधार पर कार्रवाई योग्य सुधारों का प्रस्ताव करता है, जिससे वैश्विक संस्थानों की वैधता बढ़ती है।
- **द्विपक्षीय निहितार्थ:** रचनात्मक संवाद, संघर्ष प्रबंधन और आपसी सामंजस्य स्थिर क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** बहुपक्षवाद और न्यायसंगत शासन को मजबूत करने से एकतरफा प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जा सकता है और स्थायी शांति और विकास में योगदान दिया जा सकता है।

समाधान और नीति महत्व

- **मौजूदा संस्थानों में सुधार:** अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी होने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय प्लेटफार्मों को मजबूत करना।
- **रणनीतिक संचार बढ़ाएँ:** विश्वास बनाने और गलत धारणाओं को रोकने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय जुड़ाव।

- **जन-केंद्रित नीतियों को बढ़ावा देना:** सभी राष्ट्रों के कल्याण, सतत विकास और समान विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- **साझा जिम्मेदारी:** विकसित देश संसाधन प्रदान करते हैं, जबकि विकासशील देश वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग करते हैं।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
वैश्विक शासन	जीजीआई और चीन-भारत सहयोग अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रभावशीलता और समानता में सुधार करता है।
क्षेत्रीय स्थिरता	द्विपक्षीय साझेदारी संभावित संघर्षों को कम करती है और एशिया और यूरेशिया में शांति को बढ़ावा देती है।
विकासशील विश्व सशक्तिकरण	एकजुटता पहल साझा विकास और वैश्विक निर्णय लेने में अधिक भागीदारी का समर्थन करती है।
बहुपक्षवाद	एससीओ, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र आधारित प्लेटफार्मों को मजबूत करने से सामूहिक समस्या-समाधान को बढ़ावा मिलता है।
दीर्घकालिक वैश्विक व्यवस्था	सहयोगात्मक नेतृत्व एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में योगदान देता है।

आगे की चुनौतियाँ

- सहयोग को बढ़ावा देते हुए रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करना।
- विविध भू-राजनीतिक संदर्भों में जीजीआई सिद्धांतों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- सामूहिक वैश्विक कल्याण के साथ राष्ट्रीय हितों को संतुलित करना।
- चीन-भारत धुरी के बाहर प्रमुख शक्तियों से एकतरफावाद और आधिपत्यवाद का मुकाबला करना।
- आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा बदलावों के बीच दीर्घकालिक क्षेत्रीय और वैश्विक विश्वास को बनाए रखना।

निष्कर्ष:

चीन और भारत, मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से, वैश्विक शासन में सुधार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव (जीजीआई) जैसी पहलों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को अधिक न्यायसंगत, जन-केंद्रित और परिणाम-उन्मुख बनाना है, जो एकतरफावाद, संरक्षणवाद और रणनीतिक अस्थिरता जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करते हैं। रचनात्मक संवाद, साझा जिम्मेदारी और क्षेत्रीय सहयोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 21वीं सदी वास्तव में बहुध्रुवीय बने, शांति, सतत विकास और मानवता के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाए।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: 2025 में भारत-रूस तेल व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) भारत ने 2025 में रूस से तेल आयात करना पूरी तरह से बंद कर दिया।

b) भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहता है, हालांकि जून-सितंबर 2025 के बीच कुछ PSU में आयात ~45% तक गिर गया है।

c) भारत ने ऊर्जा आयात के कारण अमेरिका पर जुर्माना शुल्क लगाया।

d) रूस अब भारत को तेल निर्यात नहीं करता है।

उत्तर : b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न। एशिया और उससे आगे शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत-चीन द्विपक्षीय कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण करें। यह बहुपक्षवाद को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? **(250 शब्द)**

Page : 09 : GS 3 : Environement / Prelims

कर्नाटक की हालिया पर्यावरणीय चुनौतियां, जिनमें कई बाघों की मौत और बढ़ते मानव-पशु संघर्ष शामिल हैं, सरकारी स्थिरता बयानबाजी और जमीनी पारिस्थितिक वास्तविकताओं के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती हैं। बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं, जैसे कि पनबिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और रेलवे परियोजनाओं को वन संरक्षण पर प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे निवास स्थान विखंडन, जैव विविधता का नुकसान और सामाजिक-पारिस्थितिक तनाव बढ़ रहा है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो विकास के उद्देश्यों को पारिस्थितिक अखंडता के साथ संरेखित करता है।

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Green rhetoric versus the practical reality

The recent deaths of six tigers at M.M. Hills and repeated cases of man-animal conflict expose Karnataka's continued prioritisation of infrastructure projects over environment, despite the loud sustainability rhetoric, argues **R. Krishna Kumar**

"The conflict incidents are a fallout of approving infrastructure projects in ecologically sensitive areas, coupled with encroachment, which is shrinking forest cover and escalating human-animal conflict in villages abutting forest boundaries"

In conflict zone: 35,580; ₹21.61; 22,483; 6,226; 3,738; 554

Forest encroachment cases in Karnataka: 44,812; 4,849; 559

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनुमोदित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वन अखंडता, जैव विविधता और वन्यजीव आवासों से समझौता करती हैं।

- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** हाथी, बाघ, तेंदुए और जंगली सूअर के हमलों के बढ़ते मामले निवास स्थान के नुकसान और अतिक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।
- **नीतिगत विरोधाभास:** जबकि आधिकारिक बयान स्थिरता पर जोर देते हैं, परियोजना अनुमोदन और विलंबित वन संरक्षण उपाय पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाते हैं।

मुख्य अवलोकन

- **बुनियादी ढांचे पर प्रभाव:** शरावती और वाराही पंप-स्टोरेज योजनाएं, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में मिनी-हाइडल परियोजनाएं और हुबली-अंकोला रेलवे लाइन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरे में डालती हैं।
- **जैव विविधता जोखिम:** वन डायवर्जन शेर-पूंछ वाले मकाक और बाघों जैसी प्रजातियों को खतरे में डालते हैं, शिकार-शिकारी गतिशीलता और प्रवासन मार्गों को बाधित करते हैं।
- **संघर्ष सांख्यिकी:** 2024-25 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की 35,580 घटनाएं दर्ज की गईं; 22,483 मामलों में हाथी शामिल हैं। वन्यजीवों और फसलों के नुकसान के कारण मानव मृत्यु दर बढ़ रही है।
- **अतिक्रमण के मुद्दे:** पूरे कर्नाटक में 44,812 से अधिक वन अतिक्रमण के मामले लंबित हैं, जिससे वन क्षेत्र और कम हो गया है और संघर्ष तेज हो गया है।
- **नीति विसंगतियां:** अनुमोदन अक्सर पारिस्थितिक विचारों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि शमन उपाय कॉस्मेटिक और अपर्याप्त होते हैं।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
पर्यावरण संरक्षण	पश्चिमी घाट और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ता है।
जैव विविधता संरक्षण	बाघ और शेर-पूंछ वाले मकाक जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां निवास स्थान के विखंडन के कारण खतरे में हैं।
मानव-वन्यजीव संघर्ष	मनुष्यों और पशुधन पर हमलों की बढ़ती घटनाएं पारिस्थितिक असंतुलन को उजागर करती हैं।
शासन और नीति	स्थिरता बयानबाजी और परियोजना अनुमोदन के बीच का अंतर पर्यावरणीय विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है।
सामुदायिक व्यस्तता	स्थानीय समुदायों को आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे संरक्षण पहल के लिए समर्थन कम हो जाता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **पारिस्थितिक निहितार्थ:** आवास विखंडन, वनों की कटाई और नदी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान दीर्घकालिक जैव विविधता और पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डालते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ:** फसल पर छापे, पशुधन की मृत्यु और मानव मृत्यु सामुदायिक आजीविका और मानव कल्याण को कमजोर करती है।
- **शासन निहितार्थ:** नीतिगत असंगति और वन संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में देरी संस्थागत विश्वसनीयता और कानून के शासन को कमजोर करता है।

- **रणनीतिक संरक्षण लेंस:** सतत विकास के लिए पर्यावरणीय अखंडता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ बुनियादी ढांचे की जरूरतों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

समाधान और नीति महत्व

- **सख्त पर्यावरण मूल्यांकन:** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले कठोर पारिस्थितिक प्रभाव आकलन लागू करें।
- **पर्यावास बहाली:** अवक्रमित या अतिक्रमित वन भूमि, विशेष रूप से हाथी और बाघ गलियारों की समयबद्ध बहाली।
- **समुदाय-केंद्रित संरक्षण:** वन संरक्षण, प्रतिपूरक उपायों और संघर्ष शमन में स्थानीय समुदायों को शामिल करें।
- **सतत विकास योजना:** न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण और परिवहन परियोजनाओं को एकीकृत करें।
- **नीति सुसंगतता:** पर्यावरण कानूनों, एनबीडब्ल्यूएल सिफारिशों और पारिस्थितिक प्राथमिकताओं के साथ राज्य-स्तरीय परियोजना अनुमोदन को संरेखित करें।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
वन्यजीव संरक्षण	लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने से पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता बनी रहती है।
मानव सुरक्षा और आजीविका	संघर्षों को कम करने से सामुदायिक कल्याण और स्थायी आजीविका सुनिश्चित होती है।
शासन की विश्वसनीयता	पारदर्शी, सुसंगत नीतियां जनता के विश्वास और पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करती हैं।
सतत विकास	पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील बुनियादी ढांचा योजना दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करती है।
पारिस्थितिक लचीलापन	वन आवरण और कनेक्टिविटी बनाए रखना पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और जलवायु लचीलापन की सुरक्षा करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- पारिस्थितिक चिंताओं पर राजनीतिक या आर्थिक प्राथमिकताओं को ओवरराइड करना।
- कई परियोजनाओं के संचयी प्रभाव से बड़े पैमाने पर आवास विखंडन।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है जिससे जीवन और संरक्षण के लिए स्थानीय समर्थन को खतरा है।
- वन अतिक्रमण के मामलों का बैकलॉग और अपर्याप्त प्रवर्तन।
- कड़े पारिस्थितिक संरक्षण और कानूनी अनुपालन के साथ विकास की मांगों को संतुलित करना।

निष्कर्ष:

कर्नाटक का पर्यावरणीय परिदृश्य नीतिगत बयानबाजी और व्यावहारिक कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, अतिक्रमण और निवास स्थान के नुकसान के साथ, मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा रही हैं और जैव विविधता को खतरे में डाल रही हैं। प्रभावी संरक्षण के लिए एकीकृत योजना, कठोर पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों, सामुदायिक जुड़ाव और लगातार नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय अखंडता के साथ विकास को समेटे बिना, स्थिरता लक्ष्य महत्वाकांक्षी बने रहते हैं, जबकि वन्यजीव और मानव समुदाय दोनों प्रतिकूल परिणाम भुगतते हैं।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न : नासिक में HAL तेजस Mk1A उत्पादन लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह भारत में तेजस एमके1ए की पहली उत्पादन लाइन है।

2. नासिक लाइन की प्रति वर्ष 8 विमानों की प्रारंभिक क्षमता है, जो प्रति वर्ष कुल अनुमानित 24 विमानों में योगदान करती है।

3. इस परियोजना ने 1,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं और इसमें 40 से अधिक उद्योग भागीदार शामिल हैं।

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: बाघों और हाथियों के आवासों के संदर्भ में कर्नाटक में जैव विविधता संरक्षण के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को संतुलित करने की चुनौतियों की जांच करें। **(150 शब्द)**

In News : GS 2 : International Relations / Prelims

युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक, समकालीन बहुध्रुवीय दुनिया में NAM की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है। संप्रभुता, स्वतंत्रता और तटस्थता को बनाए रखने के लिए शीत युद्ध के दौरान स्थापित, एनएएम दक्षिण-दक्षिण सहयोग, डिजिटल इक्विटी और सतत विकास के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। भारत, एक संस्थापक सदस्य के रूप में, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को फिर से मजबूत करने की वकालत करना जारी रखता है।

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** प्रमुख शक्ति ब्लॉकों के प्रभुत्व वाली दुनिया में, छोटे और विकासशील देशों को अपनी संप्रभुता का दावा करने, सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन को प्रभावित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** संतुलित स्वायत्तता, न्यायसंगत विकास और जलवायु, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एनएएम का उपयोग एक मंच के रूप में करना।
- **भारत की भूमिका:** बहुध्रुवीयता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को मजबूत करना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और प्रमुख शक्तियों का विरोध किए बिना वैश्विक साझेदारी की वकालत करना।

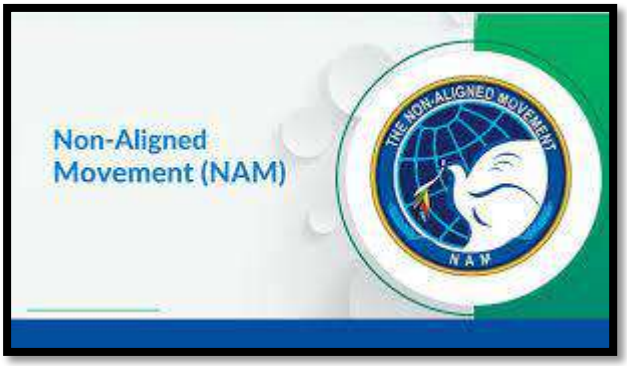

मुख्य अवलोकन

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** एनएएम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, जो 1955 के बांडुंग सिद्धांतों में निहित थी, जिसका नेतृत्व नेहरू, नासर, टीटो, सुकर्णो और नक्रुमा ने किया था।
- **सदस्यता और प्रभाव:** 120 देश (53 अफ्रीका, 39 एशिया, 26 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, 2 यूरोप), 17 पर्यवेक्षक, 10 पर्यवेक्षक संगठन; संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के ~60% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **संरचना और कार्यप्रणाली:** स्थायी सचिवालय, चार्टर, या बजट के बिना संचालित होता है; आम सहमति और घूर्णी नेतृत्व के आधार पर निर्णय।
- **समकालीन फोकस:** डिजिटल इक्विटी, वैश्विक शासन सुधार, जलवायु लचीलापन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सतत विकास।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता	बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखता है।

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
वैश्विक शासन	गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक आवाज प्रदान करता है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग	विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी, व्यापार और जलवायु लचीलापन पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति	भारत बहुपक्षवाद को बढ़ावा देते हुए प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित जुड़ाव बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लाभ उठाता है।
सतत विकास	गुटनिरपेक्ष आंदोलन जलवायु कार्रवाई, डिजिटल विभाजन और न्यायसंगत विकास सहित 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **रणनीतिक निहितार्थ:** NAM विकासशील देशों के लिए स्वायत्तता पर जोर देने, आम चुनौतियों पर सहयोग करने और वैश्विक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **भारत की भूमिका:** दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक शासन सुधारों पर पहल करते हुए प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ाव को संतुलित करना।
- **नीतिगत निहितार्थ:** शीत युद्ध के ब्लॉक से एक आधुनिक मंच के रूप में NAM का विकास बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए अनुकूलनशीलता, प्रासंगिकता और अवसर को दर्शाता है।
- **वैश्विक प्रभाव:** NAM के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई डिजिटल इक्विटी, जलवायु लचीलापन और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ा सकती है, जिससे सदस्य देशों और व्यापक वैश्विक समुदाय दोनों को लाभ हो सकता है।

समाधान और नीति महत्व

- **एनएएम को पुनर्जीवित करना:** 21वीं सदी में एक प्रासंगिक, सक्रिय मंच के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** प्रौद्योगिकी साझाकरण, व्यापार साझेदारी और जलवायु कार्रवाई पहल को मजबूत करना।
- **डिजिटल समानता और सतत विकास:** विकासशील देशों के वैश्विक डिजिटल विभाजन और जलवायु संबंधी कमजोरियों को संबोधित करना।
- **बहुपक्षीय वकालत:** संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन संस्थानों में सुधारों को प्रभावित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सामूहिक आवाज का लाभ उठाना।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
वैश्विक शासन	गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करता है।
क्षेत्रीय सहयोग	प्रौद्योगिकी और व्यापार में दक्षिण-दक्षिण साझेदारी और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देता है।
रणनीतिक स्वायत्तता	गुटनिरपेक्षता और संतुलित विदेश नीति जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है।
सतत विकास	जलवायु लचीलापन, स्वास्थ्य और समान विकास में सहयोगात्मक प्रयासों का समर्थन करता है।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था	सदस्य देशों की सामूहिक एजेंसी को मजबूत करता है, एकल शक्तियों के प्रभुत्व को कम करता है।

□□□□□ □□□□□

आगे की चुनौतियाँ

- अलग-अलग प्राथमिकताओं के साथ विविध सदस्य देशों के बीच एकता बनाए रखना।
- 21वीं सदी के भू-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में एनएएम की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना।
- वैश्विक सत्ता की राजनीति में व्यावहारिक जुड़ाव के साथ गुटनिरपेक्षता को संतुलित करना।
- सदस्यों के बीच डिजिटल विभाजन, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी अंतराल को प्रभावी ढंग से संबोधित करना।
- बहुपक्षीय मंचों में आम सहमति को मूर्त कार्यों में बदलना।

निष्कर्ष:

19वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक गुटनिरपेक्षता के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग, डिजिटल समानता, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधारों को बढ़ावा देकर, एनएएम विकासशील देशों के लिए सामूहिक एजेंसी का प्रयोग करने का एक मंच बना हुआ है। भारत की सक्रिय भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि स्वायत्तता, तटस्थता और बहुपक्षीय साझेदारी के सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रासंगिक मंच के रूप में विकसित हो।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्यों में से था?

1) भारत

2) मिस्र

3) यूगोस्लाविया

4) इंडोनेशिया

5) घाना

विकल्प:

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 2, 3, 4, 5

c) 1, 2, 4, 5

d) 1, 3, 4

उत्तर : b)

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: गंभीर रूप से विश्लेषण करें कि डिजिटल डिवाइड, जलवायु परिवर्तन और न्यायसंगत विकास जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनएएम को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में भारत की संभावित नेतृत्व भूमिका का आकलन करें। **(150 शब्द)**

Page : 06 Editorial Analysis

The next steps for Afghanistan after the New Delhi visit

Tara Kartha
is a former Director, National Security Council Secretariat

The visit of Afghanistan's Acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi and its attendant excitement in mainstream and social media are now over. But this is only the beginning. What must follow is a step-by-step engagement, with the single objective of stabilising a devastated country, and, in the process, ensuring that New Delhi projects its credentials as a humanitarian force to reckon with. In these days of rampant war and war mongering, that counts. In addition, there are issues of strong security interests, that in fact, need not be a zero sum game with Pakistan. In fact, it might just deliver a certain stability to Pakistan as well, provided that it is ready to accept it.

Terror and the realities on the ground

The joint statement between the two sides, which angered Islamabad, only reiterated the Taliban's immediate condemnation of the Pahalgam attack (April 2025), and, similarly, reiterated promises by Kabul to never allow its territory to be used against India. That promise has been made often to the international community. This has been acknowledged by the United Nations Security Council Sanctions Monitoring Committee Report which commends the Taliban's actions against the Islamic State-Khorasan (IS-K), even while it questions Kabul's actual capability in countering it – given the reclusive Mullah Haibatullah's penchant for running a parallel regime from Kandahar.

The report also notes that while the leader of the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) leader, Noor Wali Mehsud, received funds from the Taliban, Kabul was hesitant to act against it, out of fears of allying itself with the IS-K.

In short, Pakistan's demands that it act against the TTP are not naive but deliberate propaganda. Rawalpindi knows its Afghanistan. While the Taliban are no saints, they are also not the crafty terrorist sponsors Rawalpindi would have everyone believe. However, getting rid of that narrative requires actions on the ground, which is where India could come in. One line of activity is to ensure that the Taliban's mostly successful drug eradication programme is knit into crop substitution programmes and that there is an end-to-end process which ensures farmers security and exports. This is urgent as reliable reports indicate an uptick in cultivation, even as meth labs sprout across the country. Given the huge drug seizures along India's borders, a comprehensive training programme by the Narcotics Control Bureau would be highly desirable. The brute force being used now to counter narcotics actions is hardly helpful to the Taliban.

India must ensure a step-by-step engagement with Afghanistan, also ensuring that it projects its credentials as a humanitarian force to reckon with

For Kabul to 'normalise', it needs the absolute basics of any city. A recent report notes that Kabul may be the first city in the world to completely run dry by 2030. Years of war have taken their toll on projects. India's reiteration of an earlier offer to build the Shahtoot dam on the Kabul river will cause alarm in Pakistan, given a reported drop of 16% in flows. The Kabul river is a part of the Indus river system, and logically should be made part of a new treaty so that all differences are ironed out. In other words, there should be a deal that benefits all, which Islamabad will find difficult to refuse. A water-starved country is hardly the most desirable neighbour.

Education for all

The issue of women's education is paramount. The few Taliban leaders who did support it such as Abdul Baqi Haqqani who were in favour of women's education were quickly replaced by hardliners such as Mawlawi Habibullah Agha.

Changing this cruel practice is vital in not just reframing the Taliban but also India's outreach. As of now, India has announced 1,000 e-scholarships for students through the Indian Council of Cultural Relations which is nowhere enough. The online option needs to be extended to all major colleges, giving them a special dispensation in terms of foreign exchange regulations.

This may also be focused on areas where India is planning to make investments. For instance, in the joint statement, mining is a key area of interest. Therefore, skills need to be developed in the country, so that a minimal Indian presence is necessary, and which creates employment in the country.

The goal of a stable country

Finally, though it is standard practice now to talk of a 'whole of government' approach, this rarely happens in practice. While the National Security Council Secretariat is meant to do this, it needs to be strengthened so that all arms of the government, including finance, water and power, are all working towards a specific objective – to ensure that Afghanistan stays friendly and stable.

This objective needs to remain constant across governments so that the fundamental principle of 'selection and maintenance of aim' is achieved with the objective of ensuring that India's relevance remains permanent and is not part of shifting policies. But there is a key problem. The Pakistan army has no stake at all in ensuring the stabilisation of Afghanistan given its continuing desire to dominate the Taliban. Ordinary Pakistanis do, and most of them are Pashtuns with business and family ties across the border.

Potential revenues from Afghanistan trade and transit is estimated at $10 billion. None of this will matter as long as Pakistan remains a security state. If a country that is repeatedly labelled as the cradle of terrorism needs to be changed, the so-called international community has to work on systemic change in Pakistan. Democracy is not just a nice aspiration. It works, almost every time.

GS. Paper 2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: अफगानिस्तान के साथ नई दिल्ली के बाद भारत के जुड़ाव और क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की हाल की नई दिल्ली यात्रा युद्धग्रस्त देश को स्थिर करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करती है। प्रतीकात्मक कूटनीति से परे, भारत का लक्ष्य रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करते हुए और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए खुद को एक विश्वसनीय मानवीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है।

समस्या अवलोकन

- **मुख्य चिंता:** अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरता, आईएस-के और टीटीपी से सुरक्षा खतरों, पानी की कमी और सामाजिक-आर्थिक नाजुकता का सामना कर रहा है।
- **भारत का रणनीतिक उद्देश्य:** क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना, मानवीय सहायता को बढ़ावा देना और अफगान क्षेत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना।
- **राजनयिक संतुलन:** अफगानिस्तान की स्वायत्तता और विकास सुनिश्चित करते हुए जुड़ाव को पाकिस्तान की संवेदनशीलता को भी समझना चाहिए।

मुख्य अवलोकन

- **सुरक्षा और आतंकवाद:** तालिबान ने पहलगाम हमले की निंदा की; काबुल ने भारत पर हमले के लिए क्षेत्र का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। संयुक् त राष् ट्र सुरक्षा परिषद ने आईएस-के के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई को स् वीकार किया है, लेकिन परिचालन सीमाओं पर ध् यान दिया।
- **नशीली दवाओं का उन्मूलन:** भारत मेथ की खेती और सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए फसल प्रतिस्थापन और नशीले पदार्थों के नियंत्रण कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है।
- **जल और बुनियादी ढांचा:** काबुल नदी पर शहतूत बांध परियोजना पानी की तत्काल कमी को दूर करती है; सिंधु जल अधिकारों के संबंध में पाकिस्तान के साथ संभावित बातचीत की आवश्यकता है।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** महिलाओं की शिक्षा और ई-छात्रवृत्ति के विस्तार की आवश्यकता है; शिक्षा को निवेश (जैसे, खनन) के साथ संरेखित करने से रोजगार और क्षमता निर्माण हो सकता है।
- **संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण:** दीर्घकालिक स्थिरता और भारत की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए वित्त, बुनियादी ढांचे और विदेश नीति में समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
क्षेत्रीय सुरक्षा	अफगानिस्तान की स्थिरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
कूटनीति और मानवीय जुड़ाव	भारत खुद को दक्षिण एशिया में एक जिम्मेदार और स्थिर भागीदार के रूप में पेश करता है।
विकास और बुनियादी ढांचा	जल परियोजनाएं, शिक्षा और कौशल निर्माण दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
सीमा पार संबंध	तालिबान पर पाकिस्तान के प्रभाव का प्रबंधन करना और अप्रत्यक्ष रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।
आर्थिक हित	व्यापार और पारगमन क्षमता ($ 10 बिलियन) स्थिर अफगान शासन और सुरक्षा पर निर्भर करती है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **रणनीतिक निहितार्थ:** अफगानिस्तान का स्थिरीकरण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, आतंकवाद का मुकाबला करता है और शत्रुतापूर्ण अभिनेताओं के बाहरी प्रभाव को सीमित करता है।
- **राजनयिक निहितार्थ:** तालिबान के साथ चरण-दर-चरण जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय एक मानवीय और रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत की छवि को बढ़ाता है।
- **आर्थिक निहितार्थ:** बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और व्यापार संबंध सतत आर्थिक विकास पैदा कर सकते हैं और अस्थिरता को कम कर सकते हैं।
- **नीति लेंस:** सरकारों के बीच दीर्घकालिक, सुसंगत नीति आवश्यक है; "संपूर्ण-सरकार" समन्वय सुरक्षा, कूटनीति और विकास पहलों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

समाधान और नीति महत्व

- **सुरक्षा सहयोग:** स्थानीय संवेदनशीलता का सीधे सामना किए बिना अफगान आतंकवाद विरोधी पहल और क्षमता निर्माण का समर्थन करें।
- **विकास कार्यक्रम:** भारतीय निवेश के साथ नशीली दवाओं के उन्मूलन से जुड़ी फसल प्रतिस्थापन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- **शिक्षा पहल:** अफगान युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ई-छात्रवृत्ति को बढ़ाना और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **राजनयिक रणनीति:** अफगान संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए, लगातार, दीर्घकालिक जुड़ाव बनाए रखना।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
क्षेत्रीय स्थिरता	अफगानिस्तान को स्थिर करने से व्यापक दक्षिण एशियाई शांति में योगदान मिलता है और सीमा पार आतंकवाद को कम किया जाता है।
मानवीय आउटरीच	भारत सहायता और विकास पहलों के माध्यम से सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि को मजबूत करता है।
आर्थिक विकास	बुनियादी ढांचा, कौशल-निर्माण और व्यापार के अवसर दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।
राजनयिक प्रभाव	चरण-दर-चरण जुड़ाव भारत को क्षेत्रीय मामलों में एक विश्वसनीय भागीदार और मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है।

दृष्टिकोण	निहितार्थ
आतंकवाद का मुकाबला	भारत के खिलाफ हमलों के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग किए जाने की संभावना को कम करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- तालिबान की आंतरिक शक्ति की गतिशीलता सहमत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को सीमित कर सकती है।
- तालिबान पर पाकिस्तान का रणनीतिक प्रभाव भारत की पहल को कमजोर कर सकता है।
- संसाधनों की कमी और प्रशासनिक क्षमता शिक्षा, बुनियादी ढांचे और नशीले पदार्थों के कार्यक्रमों में बाधा डाल सकती है।
- उत्तरोत्तर भारत सरकारों में नीति की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- एक अस्थिर क्षेत्र में कठिन सुरक्षा चिंताओं के साथ मानवीय जुड़ाव को संतुलित करना।

निष्कर्ष:

नई दिल्ली यात्रा के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव मानवीय सहायता, सुरक्षा सहयोग और राजनयिक प्रभाव के रणनीतिक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अफगानिस्तान को स्थिर करने के लिए विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय संवेदनशीलता को नेविगेट करते हुए शासन, विकास और शिक्षा क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। दीर्घकालिक, निरंतर जुड़ाव भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा और आर्थिक और सुरक्षा लाभ उत्पन्न करेगा, जिससे एक सुरक्षित और अधिक लचीला दक्षिण एशिया में योगदान मिलेगा।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

NITIN SIR CLASSES

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

NITIN SIR CLASSES
KNOW YOUR TEACHERS
Nitin sir Classes
HISTORY + ART AND CULTURE
GS PAPER I
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
SOCIETY + SOCIAL ISSUES
GS PAPER I
NITIN KUMAR SIR
SHABIR SIR
POLITY + GOVERNENCE + IR + SOCIAL JUSTICE
GS PAPER II
NITIN KUMAR SIR
GEOGRAPHY
GS PAPER I
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ANUJ SINGH SIR
ECONOMICS
SCI & TECH
GS PAPER III
SHARDA NAND SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
INTERNAL SECURITY + ENG. (MAINS)
GS PAPER III
ARUN TOMAR SIR
ENVIRONMENT & ECOLOGY AND DISASTER MANAGEMENT
GS PAPER III
DHIPRAGYA DWIVEDI SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ETHICS AND APTITUDE + ESSAY + CURRENT AFFAIRS
GS PAPER IV
NITIN KUMAR SIR
CSAT
YOGESH SHARMA SIR
HISTORY
OPTIONAL
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
GEOGRAPHY
OPTIONAL
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
PSIR + PUBLIC ADMINISTRATION
OPTIONAL
NITIN KUMAR SIR
SOCIOLOGY
OPTIONAL
SHABIR SIR
HINDI LITERATURE
OPTIONAL
PANKAJ PARMAR SIR
https://www.facebook.com/ nitinsirclasses
https://www.youtube.com/@nitinsirclasses8314
http://instagram.com/k.nitinca
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**